

## बजट स्पेशल भाग - 2

**15. सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों और व्यापारियों का सशक्तिकरण**

- हाल ही में सिर्फ 59 मिनट में रु. 1 करोड़ तक के ऋण की योजना शुरू की गई है। जीएसटी-रजिस्टर्ड एसएमई इकाईयों को 1 करोड़ की वृद्धिशील ऋण पर 2% ब्याज की छूट मिलेगी।
- 2017 गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस की स्थापना की थी। इसके जरिए सरकारी खरीद की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी, सबको साथ लेकर चलने वाली और दक्ष होकर रूपान्तरित हो गई है। एमएसएमई भी अपने उत्पाद जीईएम के माध्यम बेच सकते हैं।
- सरकार ने हाल ही में औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग को “खुदरा व्यापार सहित आंतरिक व्यापार का संवर्धन और व्यापारियों एवं उनके कर्मचारियों का कल्याण” नामक विषय सौंपा है। अब इस विभाग का नाम ‘उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग’ हो जाएगा।

**16. रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण**

2019-20 में रक्षा बजट पहली बार रु. 3 लाख करोड़ से अधिक हो जाएगा।

**17. अवसंरचना का विकास**

- अवसंरचना किसी भी देश के विकास और अच्छे जीवन-स्तर की रीढ़ है। चाहे राजमार्ग हों या रेलवे या एयरवे या डिजि-वे ही क्यों न हों।
- आज सामान्य नागरिक भी “उड़ान” योजना के कारण हवाई जहाज में सफर कर पा रहा है। सिक्किम में पेक्योंग हवाई अड्डे की शुरुआत के साथ ही प्रचालनरत हवाई अड्डों की संख्या 100 से अधिक हो गई है।
- घेरलू हवाई यातायात पिछले पांच वर्षों में दुगुना हो गया है जिसके फलस्वरूप रोजगार भी भारी संख्या में पैदा हुआ है।
- आज, प्रति दिन 27 कि.मी. राजमार्ग के निर्माण के चलते भारत विश्व में सबसे तेज राजमार्ग विकसित करने वाला देश बन गया है। दिल्ली के आस-पास पूर्वी पेरिफेरल राजमार्ग अथवा असम और अरुणाचल प्रदेश में बोगीबाल रेल-सह-सड़क पुल जैसी दशकों तक रुकी हुई परियोजनाएं पूरी की गई हैं।
- देश के तटीय क्षेत्र में सागर माला के फ्लैगशिप कार्यक्रम से पत्तनों का विकास होगा जिससे आयातों और निर्यातों का प्रबंधन करने में तेजी आएगी।
- ब्रॉड गेज लाइनों पर सभी मानवरहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया गया है। पहली देश में ही विकसित और विनिर्मित सेमी हाई स्पीड “वंदे भारत एक्सप्रेस” को चलाने से भारतीय यात्रियों को गति, सेवा और सुरक्षा का विश्व स्तरीय अनुभव प्राप्त होगा।
- नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन स्थापित किया गया है, जो पहला संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। भारत की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता पिछले पांच वर्षों में दस गुना से अधिक हो गई है।

पूर्वोत्तर की जनता को भी अवसंरचना विकास के लाभ मिले हैं। अरुणाचल प्रदेश हाल ही में हवाई मार्ग के मानचित्र पर दर्ज हुआ है तथा मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पहली बार भारत के रेल मानचित्र पर उभरे हैं।

**18. डिजिटल इंडिया क्रांति**

- जन-धन-आधार-मोबाइल ( जेएएम) तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने दूरगामी परिवर्तन किए हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 50 वर्ष पहले किया गया था लेकिन देश का अधिकांश हिस्सा औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के अभाव में आर्थिक मुख्यधारा से अभी तक अछूता था।
- पिछले पांच वर्षों, में लगभग 34 करोड़ जन धन बैंक खाते खोले गए हैं। आधार को अब सार्वभौम तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है। इससे बिचौलियों को समाप्त करके गरीब और मध्यम वर्ग को सीधे उनके बैंक खातों में धन जमा करके सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने में मदद मिली है।

**19. मनोरंजन**

- मनोरंजन उद्योग एक प्रमुख रोजगार सृजक क्षेत्र है। मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फिल्मों की शूटिंग आसान करने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सुविधा जो केवल विदेशी फिल्म निर्माताओं के लिए उपलब्ध थी, अब भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए भी उपलब्ध कराई जा रही है।
- विनियामक प्रावधान विशेषकर फिल्मों को मंजूरी देने के लिए स्व-घोषणा पर अधिक निर्भर रहेंगे पाइरेसी की समस्या को नियंत्रित करने के लिए सिनेमाटोग्राफ अधिनियम में एंटी कैमकॉर्डिंग प्रावधानों को भी शामिल करेंगे।

**20. करदाताओं के लाभार्थ प्रत्यक्ष कर प्रणाली का सरलीकरण**

- बुनियादी छूट की सीमा 2 लाख रु. से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी और कर में छूट दी। 2.5 लाख रु. से 5 लाख रु. तक की कर स्लैब के लिए कर की दर में कमी कर 10% से 5% भी कर दिया और वेतनभोगी वर्ग के लिए रु. 40,000 की मानक कटौती शुरू की।
- धारा 80C के अंतर्गत बचत की कटौती को 1 लाख रु. से बढ़ाकर 1.5 रु. लाख कर दिया गया। जिस मकान में रह रहे हों, ऐसी गृह संपत्ति के लिए ब्याज की कटौती को 1.5 रु. लाख से बढ़ाकर 2 रु. लाख कर दिया गया।
- छोटे व्यापारियों और स्टार्ट अप के लिए विशेष लाभ और प्रोत्साहन भी दिए गए। अनुपालन की पूरी प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया। व्यापार के पूर्वानुमानित कराधार के लिए प्रारंभिक सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई। आरंभिक सीमा 50 लाख रुपए करके पहली बार पूर्वानुमान कराधान का लाभ छोटे पेशेवरों को दिया गया। कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पूर्वानुमान लाभ दर 8% कर दी गई है।
- जिन करदाताओं की कर योग्य वार्षिक आय 5 लाख तक है उन्हें कर में पूर्ण रूप से छूट मिलेगी और इसलिए उन्हें किसी प्रकार का आयकर देने की आवश्यकता नहीं होगी।
- वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है।
- बैंको/डाकघरों में जमा धनराशियों से अर्जित ब्याज पर स्रोत पर कर की कटौती की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 40,000 की जा रही है।
- आयकर अधिनियम की धारा 54 के तहत पूंजी-गत लाभ के पुनर्निवेश पर मिलने वाली छूट का दायरा 2 करोड़ तक के पूंजी-गत लाभ अर्जित करने वाले करदाताओं के लिए आवासीय मकान से दो आवासीय मकान में पुनर्निवेश तक बढ़ाया जाएगा।

**20. उपभोक्ताओं और व्यापारियों के लाभ के लिए जीएसटी में सुधार**

- जीएसटी के कारण कर के आधार में बढ़ोत्तरी हुई है, ज्यादा कर वसूली हुई हैं और व्यापार में सुगमता आई है। जीएसटी से रोजमरा के प्रचालनों और मूल्यांकनों के लिए कर-दाता और सरकार के बीच का संपर्क कम होगा। अब विवरणियां पूरी तरह आनलाइन भरी जाती हैं और ई-वे बिल सिस्टम की व्यवस्था की गई है।
- जीएसटी से पहले के समय में अनेक वस्तुओं पर लगाया जाने वाले अधिक कर को युक्तिसंगत बनाया गया है और उपभोक्ताओं विशेषकर गरीबों और मध्यम वर्ग पर प्रभारित कर के भार में काफी कमी की गई है।
- गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा रोजमर्रा इस्तेमाल की जाने वाली अधिकांश वस्तुएं अब 0% या 5% के कर-स्लैब में हैं।
- जीएसटी का उद्देश्य छोटे व्यापारियों, विनिर्माताओं और सेवा प्रदाताओं को लाभ पहुंचाना है। छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी से छूट 20 लाख से दोगुनी कर 40 लाख कर दी गई है।
- इसके अलावा, 1.5 करोड़ तक का कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को एक आकर्षक कंपोजीशन स्कीम की पेशकश की गई जिसमें वे केवल एक वार्षिक विवरणी में 1% की समान दर से कर अदा करते हैं।
- इसी प्रकार 50 लाख रु. तक के छोटे सेवा प्रदाता अब कंपोजीशन स्कीम का विकल्प दे सकते हैं और 18% की बजाय 6% की दर से जीएसटी का भुगतान कर सकते हैं।



**22. काले धन के खिलाफ अभियान और नोटबंदी**

- पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान काला धन कानून, भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, और नोटबंदी के रूप में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से 1,30,000 करोड़ के मूल्य की आस्तियां कर के दायरे में आई हैं, लगभग 50,000 करोड़ की परिसंपत्तियां जब्त और कुर्क की गई हैं और बड़ी मात्रा में नकदी रखने वाले लोगों को अपनी आय के साधन बताने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
- 2017-18 में प्रत्यक्ष कर संग्रहण में 18% की वृद्धि और कर आधार में वृद्धि हुई है जब वित्त वर्ष 2017-18 में पहली बार 1.06 करोड़ लोगों ने आय कर विवरणी दाखिल की।

**23. अगले दशक के लिए विज़न**

- अगले पांच वर्षों में भारत 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनने वाला है और इसके बाद अगले 8 वर्षों में 10 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा गया है।
- इस विज़न का पहला आयाम 10 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था और सहज-सुखद जीवन के लिए भौतिक तथा सामाजिक अवसंरचना का निर्माण करना होगा।
- हमारे विज़न का दूसरा आयाम एक डिजिटल भारत का निर्माण करना है। जो अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र, देश के कोने-कोने में पहुंचेगी और हम सभी भारतवासियों की जिंदगी को प्रभावित करेगी।
- भारत को हरी भरी धरती और साफ स्वच्छ नीले आसमां वाला एक प्रदूषण मुक्त राष्ट्र बनाना हमारी विज़न का तीसरा आयाम है।
- आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ग्रामीण औद्योगिकीकरण का विस्तार करके बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करना हमारी विज़न का चौथा आयाम है।
- हमारी नदियां और जलाशय हमारे जीवन के आधार हैं। गंगा नदी को साफ करने के लिए हमारी सरकार ने अथक प्रयास किए हैं। 2030 के भारत के लिए हमारे विज़न का पांचवां आयाम स्वच्छ नदियां हैं।
- तटवर्ती इलाकों में बढ़ी संख्या में रह रहे लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने और उनकी सार्थक जिंदगी सुनिश्चित करने हेतु, विशेष रूप से “ब्लू इकोनोमी” का दोहन करके, भारत की लंबी तटरेखा अर्थव्यवस्था की शक्ति बन सकती है।
- हमारे विज़न का सातवां आयाम हमारा अनंत आकाश है। हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम-गगनयान, भारत दुनिया के उपग्रहों को छोड़ने के लिए “लांच पैड” बन गया है और 2022 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजना हमारे विज़न के आयाम को दर्शाता है।
- खाद्यान्न में भारत को आत्म निर्भर बनाना, विश्व की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्व को खाद्यान्न निर्यात करना और सर्वाधिक जैविक तरीके से खाद्यान्न पैदा करना हमारे विज़न का आठवां आयाम है।
- स्वस्थ भारत हमारे विज़न का नौवां आयाम है। आरोग्यकर वातावरण और आवश्यक स्वास्थ्य अवसंरचना के समर्थन के साथ एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना शुरू की है।
- दसवें आयाम में भारत को न्यूनतम सरकार अधिकतम अभिशासन वाले राष्ट्र में बदलना शामिल है।
- इस व्यापक दस आयाम वाले विज़न के साथ, हम एक ऐसे भारत की रचना करेंगे जहां गरीबी, कुपोषण, गंदगी और निरक्षरता का नामोनिशान नहीं होगा। भारत एक आधुनिक, प्रौद्योगिकी चालित, उच्च विकास, समरसतापूर्ण और पारदर्शी समाज होगा।

